



## Status of Primary Education in Government and Non-Government Schools of Lucknow: A Sociological Study

ALKA GAUTAM

MPHIL

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

**सार-** सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूल की हम बात करे तो एक बहुत बड़ा अन्तर देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सरकारी स्कूल के बच्चे निम्न परिवार के पढ़ने आते है और गैर सरकारी स्कूल में उच्च परिवार तथा मध्यम परिवार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं क्योंकि सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों की सबसे प्रमुख समस्या यह है कि गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिका अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। जैसे---कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव, अध्यापक दिवस, बाल दिवस, नृत्य कार्यक्रम, त्यौहार उत्सव, व्यक्तिगत स्टेशनरी, शॉप, डायरी एवं प्रतियोगिताओं आदि के नाम पर। गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस वसूली को रोकने के लिए अभिभावकों द्वारा ठोस कदम भी नहीं उठाए जाते हैं और वह खुशी-खुशी फीस अदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है फिर भी अभिभावक सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेजना चाहते। अभिभावकों का मानना है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा उचित रूप से नहीं दी जाती है तथा शिक्षकों का भी अभाव है जिसके कारण विद्यार्थी उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गैर सरकारी विद्यालयों की शिक्षा दिन-प्रतिदिन उच्च होती जा रही है। सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं (शौचालय, पीने योग्य पानी) तो है, लेकिन शौचालयों को प्रतिदिन साफ नहीं किया जाता तथा खेलने के लिए छोटे खेल के मैदान हैं वहीं दूसरी ओर गैर सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का विशेष प्रबंध है।

दरसअल हकीकत तो यह है कि वर्तमान में जिस तरह से गैर सरकारी विद्यालयों को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे सरकारी विद्यालयों एवं उसकी शिक्षा व्यवस्था को किनारे हो होना ही है। सरकारी शिक्षा को लेकर आम जन के मन में जो छवि बनी हुई है उससे कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं भेजना चाहते और जो अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं उन्हें ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है उपरोक्त कथन ही इस अध्ययन की प्रमुख समस्या है।

**कीवर्ड -** सरकारी स्कूल , गैर सरकारी स्कूल , मूलभूत सुविधाएँ , फीस , अभिभावक , बच्चे

शिक्षा जीवन का संपूर्ण सार है। शिक्षा मानव के सामाजिक जीवन की आधारशिला है। शिक्षा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति का एक सामाजिक साधन है, जिससे समाज अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करता है अर्थात् शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानवीय गुणों का विकास कर उसे सामाजिक प्रगति तथा सामंजस्य में भागीदार बनाना है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन को तार्किक बनाती है और अच्छे बुरे कि समझ पैदा कर निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण करना है जो अपने दायित्वों का निर्वहन स्वतंत्र रूप से कर सके। भारत में शिक्षा और ज्ञान के महत्व को प्राचीन काल से ही समझा गया है।

भारतीय ऋषि अविद्या एवं अशिक्षा को मृत्यु तुल्य मानते हैं। “ज्ञानम् तृतीयम् मनुजस्य नेतम्” अर्थात् वैदिक काल से ही शिक्षा को वह प्रकाश माना गया है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है इसलिए विद्वानों ने शिक्षा को तीसरा नेत्र कहा है।

शिक्षा वस्तुतः वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य बेहतर बनता है और विश्व को और बेहतर बनाने का संकल्प और कौशल अर्जित करता है। शिक्षा व्यक्ति को केवल ज्ञान ही नहीं देती बल्कि उनका निर्माण भी करती है अर्थात् शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के ज्ञान चरित्र और व्यवहार को निर्मित एवं परिवर्तित किया जाता है। चरित्र निर्माण और नैतिकता के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इन सबसे (चरित्र निर्माण एवं नैतिकता) व्यक्ति सत्यम शिवम सुंदरम् (Truth, Beauty & Goodness) का साक्षात्कार कर अच्छे से अच्छा आचरण करता है। शिक्षा से व्यक्ति में आत्मनिर्भरता, आत्मिक ऊर्जा और अपने अस्तित्व का एहसास होता है। शिक्षा के इसी महत्व को स्वीकार कर पूर्व साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है, यह एक सर्वविदित सत्य है कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विकास की दूरी होती है।

शिक्षा का संबंध सिर्फ साक्षरता से नहीं है अपितु शिक्षा चेतना और उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करने वाला औजार है। शिक्षा के मामले में प्रारंभ से ही भारतवर्ष का दुनिया में प्रमुख स्थान रहा है। प्राचीन काल में भारत को जगतगुरु की संज्ञा दी गई थी। नवजात शिशु असहाय तथा असामाजिक होता है शिक्षा इस शिशु का सर्वांगीण विकास करके उसे अपने जीवन में विभिन्न उत्तरदायित्वों के समुचित ढंग से निर्वाह करने के योग्य बनाती है। आज के बच्चे ही देश का भविष्य हैं, वर्तमान शिक्षा का प्रयत्न मात्र उपलब्धियां देना, विद्यार्थियों को नौकरी योग्य बनाना या किसी व्यापार से जोड़ना नहीं है अपितु उन्हें जीवन-सागर में जूझने के लिए तैयार करना है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा कृत्रिम होती है तथा इसके समस्त साधन समिति होते हैं और ऐसे शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख साधन विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय इस दिशा में पहला कदम है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों में प्राथमिक शिक्षा विकास के उद्देश्यों में उस मां की तरह है जो अंगुली पकड़ कर ना केवल बच्चे को चलना सिखाती है बल्कि प्रथम बार उसमें आत्मविश्वास को रोपित करती है।

माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के विकास का आधार प्राथमिक शिक्षा ही है जितना ही इसका (प्राथमिक शिक्षा) प्रसार, विकास और उन्नति होगी उतनी ही ऊपर के स्तर की शिक्षाओं की भी प्रगति होगी।

शिक्षा मानव की एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जो उसके बौद्धिक एवं व्यक्तित्व को विकसित करती है चाहे वह प्राथमिक स्तर की हो या उच्च स्तर की। शिक्षा द्वारा किसी देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा औद्योगिक विकास संभव होता है अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा वर्तमान एवं भविष्य के लिए अद्भुत निवेश है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में शिक्षा एक अनिवार्य अंग है जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को कायम रखा जा सकता है क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही समाज में व्याप्त समानता, भेदभाव तथा अक्षमता को दूर किया जा सकता है।

अतः शिक्षा लोकतांत्रिकरण की एक प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य समाज में समानता लाना तथा लोगों के विभिन्न वर्गों एवं समुदायों के बीच सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना है।

अतः देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण विधानसभा और सांसद में ना होकर विद्यालयों में हो रहा है। राष्ट्रीय जीवन में भी शिक्षा अति आवश्यक है अर्थात् विद्यालय ही वह स्थान है जहां विद्यार्थियों को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाया जाता है।

### **‘भारत में प्राथमिक शिक्षा’ - श्री जगदीश चंद्र अग्रवाल (2006)**

संभवतः प्राथमिक शिक्षा पर यह पहली पुस्तक है जिसमें इसके विविध पक्षों पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तथा शैक्षिक समितियों और आयोगों की संस्तुतियों के संदर्भ में प्रकाश डाला गया है। स्वतंत्रता के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास की गति अधिक तीव्र रही है और उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं। इन सबका समावेश इस पुस्तक में है। 'सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा' के लक्ष्य की प्राप्ति में जो-जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका सविस्तार विवेचन करके उनको दूर करने के लिए ठोस सुझाव भी प्रस्तुत हैं।

**'शैक्षिक समाजशास्त्र' - डॉ. रामनाथ शर्मा (2006)**

शिक्षा व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियों को विकसित करने की प्रक्रिया है जबकि समाज मानव सम्बन्धों की एक परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। समाज के विकास में शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है। शिक्षा सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं और सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूप को प्रभावित करती है। इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए ही समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शैक्षिक समाजशास्त्र को शामिल किया गया है। सभी समाजशास्त्री यह मानते हैं कि शैक्षिक क्षेत्र में समाजशास्त्रीय अध्ययनों की व्यापक संभावनाएँ हैं और विद्यालय समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयोगशाला का कार्य कर सकते हैं। प्रस्तुत पुस्तक शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा के सामाजिक पहलू के विभिन्न तत्त्वों के स्वरूप, महत्व और सामान्य सिद्धान्तों को स्पष्ट करने की एक सफल कोशिश है। प्रस्तुत पुस्तक निम्न छः खण्डों में विभाजित की गयी है: प्रथम खण्ड- विषय-प्रवेश शिक्षा के अर्थ, प्रकृति, प्रकार और कार्य शिक्षा के उद्देश्य भावात्मक एकता और शिक्षा अंतरसंस्कृति अवबोध और शिक्षा राष्ट्रीयता और शिक्षा अंतरराष्ट्रीय और शिक्षा आर्थिक वृद्धि के लिये शिक्षा। द्वितीय खण्ड- शिक्षा के प्रकार, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, समाज शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा। तृतीय खण्ड- शिक्षा के साधन, शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधन, राज्य और शिक्षा, नागरिकता के लिये शिक्षा, प्रजातन्त्र और शिक्षा। चतुर्थ खण्ड- नवीन प्रवृत्तियों का शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति, शिक्षा में समाहारक प्रवृत्ति। पंचम खण्ड- शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार, शैक्षिक समाजशास्त्र, भारतीय समाज की प्रवृत्ति और प्रभाव, शिक्षा में व्यक्ति और समाज, शिक्षा और समाज, विद्यालय और समुदाय, मूल्य और शिक्षा, सामाजीकरण और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा समाजशास्त्र में रुचि रखने वाले भी इसे अवश्य पसंद करेंगे।

**'आधुनिक शिक्षा और दलित' - अरुण कुमार (2015)** शिक्षा व्यक्ति के जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। शिक्षा के विकास के बिना विकास की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। शिक्षा विकास की रीढ़ है। अच्छी शिक्षा अच्छे समाज का निर्माण करती है, दूसरी ओर अच्छा समाज भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रतिरूपित करता है। भारत जैसे विषमता मूलक समाज में जहाँ प्रत्येक दृष्टिकोण से पिछड़े दलित वर्ग हैं वहाँ असमानता की खाई को पाटकर समाज में जागरूकता उत्पन्न कर एकता के सूत्रा में पिरोने के लिये शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। इस पुस्तक में दलित वर्ग की शैक्षणिक दशा का सटीक उल्लेख किया गया है। शिक्षा का समग्रता से अवलोकन करने के लिये इसके सहायक पहलू - सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य इत्यादि के परिप्रेक्ष्य का परीक्षण करना आवश्यक है। इसलिये इस पुस्तक में दलित वर्ग के इन सभी पहलुओं की विषद व्याख्या की गई है। दलितों पर शिक्षा के बहुआयामी प्रभाव क्या हैं? उदारीकरण, भूमंडलीकरण के मानचित्र में दलितों का शैक्षणिक परिदृश्य कैसा है? दलित उत्थान में शिक्षा की भूमिका क्या है? शिक्षा प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में दलितों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ क्या हैं? इन चुनौतियों का समाधान तथा संभावनाएं क्या हैं? इत्यादि मुद्दों का समुचित उल्लेख प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है।

**अध्ययन का उद्देश्य** सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के स्तर की पठन- पाठन की क्रिया का पता लगाना। सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के स्तर की मूलभूत सुविधाओं का पता लगाना। सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के स्तर की फीस का पता लगाना।

**शोध प्रविधि [Research Method]** शोध कार्य से संबंधित कुछ प्रमुख शोध प्रविधिओं की सहायता ली गई है। साक्षात्कार अनुसूची (प्रश्नों की एक सूची) के जरिए आंकड़ों का संकलन किया गया है जिसके आधार पर उपकल्पनाओं का प्रशिक्षण किया है कुछ निदर्शनों का चुनाव करके शोध संबंधी सूचनाओं एवं आंकड़ों को संकलित किया। इसके अलावा प्रस्तुत शोध में प्राथमिक स्रोत (field work) एवं द्वितीयक स्रोत (books, net, article) के द्वारा संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जिसके आधार पर ही शोध के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सका है। शोध प्रविधि को विभिन्न चरणों में प्रस्तुत किया गया है जो कि इस प्रकार हैं -

**अध्ययन क्षेत्र [Study Area]** प्रस्तुत शोध के अध्ययन के लिए बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के आसपास 10 गैर सरकारी तथा 6 सरकारी विद्यालयों में से 3 सरकारी एवं 3 गैर सरकारी विद्यालयों को अध्ययन के लिए चुना है।

**अध्ययन रेखा-चित्र (Study Design)** प्रस्तुत शोध के अध्ययन रेखा चित्र में मात्रात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया गया है।

**निदर्शन का आकार (Sampling Size)** प्रस्तुत शोध में तीन सरकारी एवं तीन गैर सरकारी विद्यालयों (प्राथमिक स्तर) का चुनाव किया गया है तथा सरकारी विद्यालय के प्राथमिक स्तर के 30 विद्यार्थियों तथा 30 गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का चुनाव किया गया है।

## निदर्शन विधि [Sampling Method]

Systematic Random Sampling Method (व्यवस्थित यादृच्छिक नमूना विधि) का उपयोग अध्ययन जनसंख्या के नमूने के चयन के लिए किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में तीन सरकारी एवं तीन गैर-सरकारी विद्यालय (प्राथमिक स्तर) हैं तथा प्रत्येक विद्यालयों की कक्षा से 10-10 विद्यार्थियों को लिया गया है।

**आंकड़ा संग्रहण की विधि [ Method of Data Collection]** साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग करके सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग अध्ययन क्षेत्र से डाटा एकत्र करने के लिए किया जाता है साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग करके सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग अध्ययन क्षेत्र से डाटा एकत्र करने के लिए किया जाता है।

**नैतिक प्रतिपूर्ति [Ethical Consideration]** डेटा संग्रह के दौरान किसी भी प्रतिवादी को जानकारी प्रदान करने के लिए मजबूर नहीं किया गया है डेटा संग्रह के दौरान उत्तर दाताओं की सुविधा पहली प्राथमिकता थी।

**वर्तमान समय में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के पठन-पाठन की शिक्षा की स्थिति :-**वर्तमान समय में सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के पठन-पाठन की स्थिति वर्तमान समय में सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक स्तर के पठन-पाठन की स्थिति गैर सरकारी की अपेक्षा ठीक-ठाक है। **सरकारी विद्यालय के प्राथमिक स्तर की पठन पाठन की स्थिति:-**सरकारी विद्यालय के प्राथमिक स्तर के पठन-पाठन की स्थिति ठीक-ठाक है। शहरी क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय होने के कारण यहां के सरकारी विद्यालयों की स्थिति बेहतर है। कुछ निम्न महत्वपूर्ण तथ्य है जो सरकारी विद्यालय के प्राथमिक स्तर की पठन-पाठन की स्थिति को दर्शाते हैं -

- RTE Act के तहत सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या तो बढ़ रही है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता रसातल में जा रही है।
- इन विद्यालयों में केवल वही छात्र आते हैं जिनके मां बाप मजदूर करते हैं अर्थात वे निम्न वर्ग के होते हैं। वे अपने बच्चों का दाखिला सिर्फ छात्रवृत्ति की लालसा के कारण करवाते हैं ताकि उनकी स्थिति में सुधार आ सके।
- सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है अर्थात विषयवार शिक्षकों का अभाव है। विशेषकर गणित, अंग्रेजी के शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ रही है।
- ज्यादातर सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक स्तर (1-5) की कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक ही साथ बैठा कर शिक्षा दी जाती है जिस कारण विद्यार्थी शिक्षा का उचित ज्ञान नहीं ले पाते हैं तथा शिक्षक अभाव के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है।
- सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थी ज्यादातर अनुपस्थित रहते हैं क्योंकि वे गरीब के चलते अन्य काम भी करते हैं।
- कुछ अभिभावक तो मात्र भोजन के लिए अपने बच्चों का दाखिला करवाते हैं क्योंकि अधिक गरीब होने के कारण उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है।
- शिक्षकों का अध्ययन में उत्साहपूर्वक हिस्सा ना लेना भी सरकारी विद्यालयों की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति (गिरती हुई शिक्षा) का प्रमुख कारण है।
- अधिकांश छात्र गरीब मजदूर परिवार के होते हैं अतः उनके माता-पिता निरक्षर या बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं जिसके कारण वे अपने बच्चों को उचित प्रारंभिक शिक्षा नहीं दे पाते और उनका उचित विकास नहीं हो पाता है।
- अध्यापक/अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जैसे- सुलेख प्रतियोगिता, खेलकूद आदि।

उपरोक्त कथनों को देखने पर यह ज्ञात होता है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति अत्यंत सोचनीय है। इन सब के बावजूद भी शहरी सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक स्तर की शिक्षा बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी कुशाग्र, चतुर एवं बुद्धिमान है। यद्यपि सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों में तथा सरकारी विद्यालयों में मूलभूत परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। यह परिवर्तन शायद शहरी क्षेत्रों के कारण ही दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी खेलकूद, प्रतियोगिताओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है तथा विशेष बदलाव भी देखे जा सकते हैं।

### गैर सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक स्तर की पठन पाठन की स्थिति:-

शहरी क्षेत्र के गैर सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के पठन-पाठन की स्थिति उच्च स्तर पर है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो शहरी क्षेत्र के गैर सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक शिक्षा के पठन पाठन की स्थिति को दर्शाते हैं-

- गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। अत्याधिक फीस होने के बावजूद भी गैर सरकारी विद्यालयों का ही बोलबाला है।
- इन विद्यालयों में केवल वे बच्चे दाखिला ले पाते हैं जिनके मां बाप आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं या वे उच्च वर्ग या कुल के होते हैं।
- गरीब मजदूर के बच्चे इन विद्यालयों में दाखिला नहीं ले सकते क्योंकि वह अनपढ़ होते हैं और उनके बच्चे शैक्षिक स्तर में पिछड़े हुए होते हैं या वे फीस भरने के काबिल नहीं होते। यही कारण है कि इन विद्यालयों के बच्चे तर्कशक्ति वाले, बुद्धिमान तथा चतुर देखे जाते हैं।
- इन विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की भरमार होती है तथा उचित शिक्षक को ही चुना जाता है। इसी वजह से गैर सरकारी विद्यालयों की प्राथमिक शिक्षा दिन-प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है।
- गैर सरकारी विद्यालयों में अलग-अलग कक्षाओं में अध्यापक/अध्यापिका हैं जो अपने-अपने विषयों में पारंगत हैं जिसकी वजह से विद्यार्थी ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेते हैं।
- इन विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन बहुत कम होता है फिर भी इन विद्यालयों में अध्यापकों की भरमार है।
- इन विद्यालयों में विद्यार्थी प्रतिदिन कक्षा में उपस्थित रहते हैं विद्यालय ना आने पर विद्यार्थियों के द्वारा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र तथा अभिभावक के हस्ताक्षर भी कराने पड़ते हैं, जिस कारण विद्यार्थी चाह कर भी अनुपस्थित नहीं हो सकता।
- शिक्षकों का उत्साहपूर्वक विद्यार्थियों को पढ़ाना तथा विद्यार्थियों को उत्साहित एवं प्रोत्साहित करना भी शिक्षा की स्थिति को बढ़ावा देता है तथा शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाते हैं।
- ज्यादातर इन विद्यालय के विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है जिससे वह ट्यूशन एवं कोचिंग का भी सहारा लेते हैं जो उनकी विद्यार्थियों की प्रारंभिक शिक्षा को और भी मजबूत बनाता है।
- गैर सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के खेलकूद, प्रतियोगिताएं आदि में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो उनके मस्तिष्क का सही विकास कर उनके मस्तिष्क को तेज करता है।
- गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अध्यापक कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं।
- इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्रों को परीक्षा से गुजरना पड़ता है तथा कुछ चयनित छात्रों का ही दाखिला किया जाता है।

उपरोक्त कथनों को देखने पर यह ज्ञात होता है कि गैर सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक स्तर के शिक्षा की स्थिति अति प्रशंसनीय है। इन विद्यालयों के विद्यार्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ होते हैं। इन विद्यालय के छात्र हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि गैर सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति उच्च स्तर पर है।

### वर्तमान समय में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की मूलभूत सुविधाओं की स्थिति:-

वर्तमान समय में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की मूलभूत सुविधाओं की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है -

## सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की मूलभूत सुविधाएं -

- सरकारी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था तो है परंतु प्रतिदिन साफ नहीं किया जाते जिसके चलते ज्यादातर बच्चे बीमारी का शिकार हो जाते हैं और वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं।
- सरकारी विद्यालयों में पीने योग्य पानी की व्यवस्था है जैसे- नल
- सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक स्तर की कुछ कक्षाओं में बैठने के लिए सीट हैं तथा कुछ विद्यालयों में सीट नहीं है वहां वे विद्यार्थी जमीन पर ही बैठ कर पढ़ाई - लिखाई करते हैं।
- सरकारी विद्यालयों में श्यामपट्ट की सुविधा भी है।
- सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी खुद विद्यालय की साफ सफाई करते हैं क्योंकि वहां कोई सफाईकर्मी नहीं है।
- यहां के विद्यार्थियों को निचले स्तर के खेल कूद करवाए जाते हैं जो नियम विरुद्ध होते हैं।
- पर्याप्त खेल के मैदान का ना होना जिसके कारण बच्चे सही से खेल नहीं पाते या खेलते ही नहीं है।
- पूर्ण रूप से कक्षाएं नहीं है जिसके कारण एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा दी जाती है।
- अध्यापकों/अध्यापिकाओं की कमी है जिसके कारण बच्चे उचित शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं।
- विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन की सुविधा, वर्दी, किताब एवं निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।
- ज्यादातर विद्यालयों में बिजली का भी अभाव है।

उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता है कि सरकारी विद्यालय के प्राथमिक स्तर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जो कि विद्यार्थियों की संख्या को दिन-प्रतिदिन कम करता चला आ रहा है। शिक्षकों के अभाव के कारण विद्यार्थी उचित ज्ञान से कोसों दूर हैं। चपरासी ना होने की वजह से विद्यार्थियों को स्वयं शौचालय एवं विद्यालय की साफ सफाई करनी पड़ती है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं ना के बराबर हैं।

**गैर सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की मूलभूत सुविधाएं-** गैर सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था है तथा यह शौचालय रोजाना साफ भी किए जाते हैं, ना साफ किए जाने पर विद्यार्थी शिकायत भी कर सकते हैं।

- प्रत्येक कक्षा में सीट है।
- प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को Sumer Camp भी ले जाया जाता है जिससे इनका मानसिक विकास तेजी से होता है।
- विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताएं नियमानुसार कराई जाती हैं।
- गैर सरकारी विद्यालयों में प्रतिदिन साफ-सफाई कराई जाती है जिससे वहां के विद्यार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से बीमार न हो।
- गैर सरकारी विद्यालयों में हर कक्षा के अलग-अलग कमरे हैं जहां विद्यार्थी सुचारू रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं।
- विषयवार शिक्षक होते हैं जो कि अपने अपने विषय में निपुण होते हैं।
- गैर सरकारी विद्यालयों में उचित बिजली की व्यवस्था है तथा बिजली चले जाने पर जनरेटर या सोलर पैनल की भी सुविधा है।
- गैर सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए 'आया' भी होती हैं जो उनकी देखभाल करती हैं।
- गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए पुस्तकालय की भी उचित व्यवस्था है।
- कंप्यूटर लैब की व्यवस्था है।
- नाट्य प्रतियोगिताएं या अन्य प्रतियोगिताओं के अभ्यास के लिए अभ्यास कक्ष की भी सुविधा है।

उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि गैर सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उचित व्यवस्था है जो की बढ़ती हुई छात्रों की संख्या का कारण है।

## निष्कर्ष (Conclusion)

प्रस्तुत शोध में आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों से अध्ययन का निष्कर्ष ज्ञात किया गया है कि वर्तमान समय में शहरी क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की स्थिति बेहतर है शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों में जोश दिखाई देने लगा है।

अतः कर सकते हैं कि सरकारी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है यही परिवर्तन सरकारी विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं (शौचालयों, पीने के लिए पानी, सीट) में भी दिखाई देता है। कक्षाओं तथा शिक्षकों का अभाव है फिर भी अध्यापक/अध्यापिका एक ही कक्षा में बैठकर 1 से 5 तक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। वहीं दूसरी और गैर सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति उच्च स्तर पर है। अधिकतम चीज के कारण मूलभूत सुविधाएं अच्छी है तथा योग्यता के आधार पर ही विषयवार शिक्षकों की नियुक्त की जाती है। अतः कह सकते हैं कि गैर सरकारी विद्यालयों की तुलना में सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बेहतर है तथा और अधिक सुधार की स्थिति देखी जा सकती है।

## संदर्भ सूची [References]

- मुखर्जी, आर.एन (2009), “सामाजिक शोध एवं संख्याकी”, विवेक प्रकाश, दिल्ली
- शर्मा, विनायक प्रेम नारायण (2011), “शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण” भारत बुक सेंटर, लखनऊ
- कुमार, अरुण (2015), “आधुनिक शिक्षा एवं दलित”, रावत पब्लिकेशंस, नई दिल्ली
- आहूजा, राम (2011), “भारतीय समाज” रावत पब्लिकेशंस, नई दिल्ली
- सिंह, हरिशंकर (2015), “स्त्री शिक्षा”, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ
- पाठक, पी. डी. (2006), “भारतीय शिक्षा और उनकी समस्याएं” विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
- सिंह, अरुण कुमार (2006), “उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान”, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या- 487
- अग्रवाल, रीना (2007), “परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की शैक्षणिक संप्राप्ति: एक अवलोकन”, भारतीय शिक्षा शोध-पत्रिका
- झा, शीतला एवं दुबे, शैलजा (2016), “माध्यम मध्यान भोजन कार्यक्रम व स्व सहायता समूह के कार्य निष्पादन पर शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन”,
- सिंह, शिव प्रकाश, (2007) “भारत में सभी के लिए शिक्षा अभियान मिथक या वास्तविकता”, प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका प्रकाशक एवं मुद्रक महेंद्र जैन, आगरा, पृष्ठ 2078-79